प्रदेश के 200 आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में होंगे विकसित

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन

केंद्र ने बजट में 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की घोषणा की थी

लखनऊ। केंद्र सरकार की ओर से बजट में देश की 1000 आईटीआई को अपग्रेड कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 200 आईटीआई योजना में लाभान्वित होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय राज्य संचालन समिति का गठन किया है।

इस समिति में व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग, अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त, एमएसएमई, श्रम, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य या प्रमुख सचिव होंगे। साथ ही क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय (आरडीएसडीई) कानपुर के क्षेत्रीय निदेशक, सेवायोजन निदेशालय के निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक, कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक, प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के कम से कम दो प्रतिनिधि, शैक्षिक व प्रशिक्षण क्षेत्र के एक विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि जल्द ही इन आईटीआई की सूची केंद्र को भेजी जाएगी। इनको हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं ग्लोबल पार्टनर की सहायता से पांच नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। केंद्र की इस योजना से प्रदेश को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की कवायद विभाग की ओर से की जा रही है। ब्यूरो